INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 2 | MARCH - 2023

कैशलेस अर्थव्यवस्था, छोटे और मध्यम व्यवसायों पर विमुद्रीकरण का प्रभाव : एक अध्ययन

डॉ. अंजना सिंह
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, त्योंथर रीवा (म.प्र.)

सारांश –

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य देश की कैशलेस मौद्रिक नीति के भारतीय छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना है। सरकार उच्च मूल्यवर्ग की मुद्राओं के विमुद्रीकरण से रोमांचित है। भविष्य में व्यापार करने के लिए सबसे टिकाऊ और पारिस्थितिक रूप से लाभकारी तरीकों में से एक है, नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से ऐसी अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करना जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों पर तेजी से निर्भर करती है। अपनी मुद्रा को विमुद्रीकृत करने के देश के हालिया निर्णय के परिणामस्वरूप, आम जनता को अपने सभी मौद्रिक लेनदेन ऑनलाइन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विमुद्रीकरण के त्वरित अपनाने से एमएसएमई क्षेत्र को नुकसान हुआ, जो पारंपरिक तरीके से अपना व्यवसाय करना पसंद करता है। कैशलेस युग में सफल होने के लिए, इस कंपनी को कड़ी नियामक निगरानी की आवश्यकता होगी। यदि एमएसएमई मौजूद नहीं होते तो आर्थिक परिवर्तनों का अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ता। एक इलेक्ट्रॉनिक मौद्रिक दर्शन डीलरों और ग्राहकों दोनों द्वारा डिजिटल बुनियादी ढांचे का अधिक बार उपयोग करने का परिणाम है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि कैशलेस समाज भारत के छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को कैसे प्रभावित करेगा। लेख के अनुसार, एमएसएमइ कैशलेस वातावरण में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, साथ ही वैकल्पिक समाधान भी।

मुख्य शब्द – कैशलेस, मौद्रिक नीति, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय।

प्रस्तावना –

जब किसी अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह ना के बराबर हो जाए तथा सभी लेन–देन डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर और रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों एवं एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस जैसे भुगतान माध्यमों से होने लगे तो यह स्थिति कैशलेस अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित की जाती है।

'भ्रष्टाचार, आतंकवाद के वित्तपोषण और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए विमुद्रीकरण को स्पष्ट रूप से लागू किया गया था। लेकिन इसे खराब तरीके से डिजाइन किया गया था, बाजार के कानूनों पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। नोटबंदी का भ्रष्टाचार से बहुत कम लेना–देना था। यह गरीब लोग और अनौपचारिक क्षेत्र है, जिस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वह स्पष्ट रूप से एक गैर–शुरुआत करने वाला था।' – कौशिक

बसु, सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार 'मुद्रा का विमुद्रीकरण एक निरंकुश कार्य था क्योंकि सरकार ने एक वचन पत्र के साथ आने वाले मुआवजे के वादे को तोड़ दिया था। नोटबंदी भरोसे के खिलाफ जाती है। यह भरोसे को कम करता है पूरी अर्थव्यवस्था का। केवल एक अधिनायकवादी सरकार ही लोगों को शांति से इस तरह का दुख दे सकती है दृ लाखों निर्दोष लोगों को उनके पैसे से वंचित किया जा रहा है और अपने स्वयं के धन को वापस पाने की कोशिश में पीड़ा, असुविधा और अपमान के अधीन किया जा रहा है। – अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता 'यह ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश और उसके विकास के स्तर के लिए किया जाना चाहिए। जापान के पास प्रति व्यक्ति सबसे अधिक नकद है, जो भारत से कहीं अधिक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रचलन में नकदी 10% थी, जबकि जापान में यह 60% है। वह काला धन नहीं है; वह भ्रष्टाचार नहीं है।' – आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ 'शैडो इकोनॉमी में काम करने वाला बहुत सारा पैसा अब बैंकिंग ढांचे का ही हिस्सा बन जाएगा। अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बैंकों के पास बहुत अधिक पैसा होगा। निजी क्षेत्र का निवेश, जिसकी अब तक कमी थी, अब अर्थव्यवस्था में वापस आ जाएगा। एनपीए की समस्या से जूझ रहे बैंकों के पास कृषि, बुनियादी ढांचा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, व्यापार और उद्योग के लिए उधार देने के लिए बहुत अधिक पैसा होगा।' दृ अरुण जेटली, भारत के पूर्व वित्त मंत्री 'काले धन को बाहर निकालने का यह एक उपयोगी तरीका है, यह देखते हुए कि नकदी का बड़ा प्रतिशत इन्हीं दो संप्रदायों में है। जिस तरह से इसे लागू किया गया वह आश्चर्य की बात नहीं है – इस तरह की कार्रवाइयां घोषित होने तक हमेशा गुप्त रहती हैं, ताकि अंदरूनी लोग बाहरी लोगों की कीमत पर जानकारी का लाभ न उठाएं।' – अरविंद विरमानी, सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार।

कैशलेस लेन–देन के प्रकार :–

मोबाइल वॉलेट : मोबाइल वॉलेट स्मार्टफोन में मौजूद एक वर्चुअल वॉलेट (आभासी वॉलेट) है, जिसमें पैसे डिजिटल मनी के रूप में रखे जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक डिजिटल पर्स है जिसमें से पैसे को निकालकर लेन–देन और भुगतान किया जा सकता है।

प्लास्टिक मनीः प्लास्टिक मनी का तात्पर्य प्लास्टिक से बने उन काड्र्स जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि से है जिनका इस्तेमाल भुगतान आदि के लिये किया जा सकता है। प्लास्टिक मनी के प्रयोग से कैशलेस अर्थव्यवस्था को बल तो मिलता ही है साथ में नकदी लेकर चलने की झंझटों से भी मुक्ति मिल जाती है।

नेट बैंकिंगः किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के माध्यम से इंटरनेट के ज़रिये प्रयोग करना नेट बैंकिंग कहलाता है। इसके लिये बैंक वेबसाइट और मोबाइल एप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। तत्काल भुगतान सेवा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर और रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट नेट बैंकिंग के तहत आने वाली भुगतान प्रणालियाँ हैं।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस : एकीकृत भुगतान इंटरफेस, राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ की गई लेन–देन की एक नई प्रणाली है जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग कर धन का त्वरित हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। यह भुगतान का एक ऐसा माध्यम है जो सातों दिन चौबीसों घंटे कार्य करता है। इस सेवा का लाभ बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी उठाया जा सकता है। इससे धन के लेन–देन में नकदी का चलन कम हो जाएगा तथा व्यापारिक भुगतान सरल सुरक्षित एवं पारदर्शी हो जाएगा।

पेमेंट बैंक : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो प्रकार के लाइसेंस जारी किये जाते हैं: सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस और विभेदित बैंक लाइसेंस। एक पेमेंट बैंक, विभेदित बैंक लाइसेंस प्राप्त बैंकों की श्रेणी में आता है। पेमेंट बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक हैं, जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है। इन बैंकों का उद्देश्य प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों, लघु कारोबारों, असंगठित क्षेत्र की अन्यक संस्थाओं को सेवा प्रदान कर अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

यदि अर्थव्यवस्था कैशलेस होती है तो टैक्स चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। ऐसा इसलिये क्योंकि प्रत्येक कैशलेस लेन–देन के प्रमाण डेटाबेस में अंकित हो जाते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आय से संबंधित आँकड़े जुटाने में आसानी होती है। कैशलेस समाज का एक मुख्य लाभ यह है

कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के ज़रिये किये गए आर्थिक लेन–देन ब्लैक मनी के बाज़ार को खत्म कर सकता है। नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी इकट्ठा करना, नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, जबरन वसूली आदि जैसे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना आसान बन जाता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था इन से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। यह प्रयास सभी को बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने में अत्यंत ही सहायक होगा। ऐसा इसलिये क्योंकि इस व्यवस्था में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु बुनियादी ढाँचा खड़ा करने के बजाय बस एक डिजिटल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु किसी स्थान विशेष पर पहुँचने की शर्त खत्म हो जाएगी, इससे ट्रांजेक्शनल (लेन–देन संबंधी) मूल्य के साथ–साथ ट्रांसपोर्ट खर्च में भी कमी आएगी। कैशलेस लेन–देन बढ़ेगा तो रिज़र्व बैंक को कम नोट छापने होंगे जिससे नोटों की छपाई पर आने वाली भारी लागत को कम किया जा सकता है। साथ ही एटीएम को सुचारू रूप से चालू रखने में बैंकों का होने वाला खर्च भी कम होगा।जनता के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि पैसे बिचौलियों के हाथ में जाने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुँचेगा।

विश्लेषण –

विमुद्रीकरण का तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की मुद्रा को संचलन से वापस लेने से है। राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन होने पर यह आवश्यक है; पुरानी मुद्रा को हटाया जाना चाहिए और नई मुद्रा इकाई के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। 1946 में पहली बार और 1978 में दूसरी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। 8 नवंबर 2016 को वर्तमान मोदी सरकार द्वारा तीसरी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है।

एक कैशलेस अर्थव्यवस्था काले धन के सिस्टम में प्रवेश करने की संभावना को कम करती है और नापाक गतिविधियों को पूरी तरह से कम करती है। नकदी आधारित अर्थव्यवस्था आम तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, जबरन वसूली आदि जैसी आपराधिक गतिविधियों को आसानी से बढ़ावा देती है। सभी जाली नोटों पर अंकुश लगाया जा सकता है। कैशलेस समाज में, कर चुकाने से बचा नहीं जा सकता है और इस उल्लंघन को बहुत कम किया जा सकता है। यह बढ़ा हुआ कर मूल्य राज्य के लिए राजस्व में वृद्धि का कारण बनता है, जिसे आगे कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त लाभों के अलावा, डिजिटल लेन–देन पारदर्शिता, जवाबदेही और बाजार दक्षता का कारण बनता है क्योंकि यह भारी मात्रा में नकदी को ले जाने और परिवहन करने के जोखिम को कम करता है। कैशलेस लेन–देन के माध्यम से हो रहे डेटा ट्रांसफर से सरकार को डेटा ट्रांसमिशन के पैटर्न से भविष्य के खर्च जैसे आवास, ऊर्जा प्रबंधन आदि की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि पैसे छापने की लागत कम हो जाती है। 2012 में आरबीआई द्वारा सूचना के अधिकार के उत्तर के डेटा से पता चलता है कि इसकी कीमत रु। 2.50 प्रत्येक रुपये मुद्रित करने के लिए। 500 मूल्यवर्ग नोट, और रु। 3.17 एक रुपये मुद्रित करने के लिए। 1,000 का नोट। अप्रैल 1994 से जून 2016 तक, मुद्रा ने 17% की वार्षिक वृद्धि दर दिखाई है, जबकि बैंक मुद्रा की हिस्सेदारी लगभग 5% रही है।

वर्ल्ड एचआर डायरी में कुणाल सेन का एक लेख इस बारे में बात करता है कि विमुद्रीकरण ने छोटे व्यवसायों को कैसे प्रभावित किया है। मीडिया आमतौर पर मानता है कि विमुद्रीकरण एक राजनीतिक सफलता रही है और लाखों लोगों का दिल जीत लिया है जो सोचते हैं कि मोदी एकमात्र राजनेता हैं जो काले धन पर कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। लंबी–लंबी कतारों में खड़े मध्यवर्गीय लोग अधिकतर एक बड़े कारण के लिए कुछ कष्ट सहने को तैयार प्रतीत होते हैं।

भारत के 100 मिलियन दुकानदारों में से मुश्किल से 2% के पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वीकार करने की मशीनें हैं: बाकी नकद आधारित हैं। अन्य छोटे व्यवसायों, ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों के लिए भी यही सच है। इन सभी के कारोबार में भारी गिरावट आई है। कई मूल्य श्रृंखला के हिस्से हैं, कच्चे माल के उत्पादकों से शुरू होकर खुदरा स्तर पर समाप्त होते हैं। एक ओर तो नोटों के अभाव में ग्राहकों ने खर्च कम कर दिया है। दूसरी ओर, व्यवसाय ऋणों के नकद पुनर्भुगतान या साप्ताहिक श्रम मजदूरी आदि के भुगतान के लिए पर्याप्त मुद्रा नोट नहीं जुटा पाते हैं। उद्यमों ने अर्थव्यवस्था में काले धन के संचलन से निपटने के कदम की सराहना की है और उम्मीद करते हैं कि यह लंबे समय में इस क्षेत्र को लाभ प्रदान करेगा। यदि उनकी वर्तमान

समस्याएँ कुछ ही सप्ताह तक रहती हैं, तो वे ठीक हो जाएँगे। यदि समस्याएं अधिक समय तक बनी रहीं, तो नुकसान काफी बड़ा होगा।

एक शीर्ष परिवहन वित्त कंपनी का कहना है कि सामान्य भुगतान का केवल 60% ही आ रहा है। कुछ सबसे छोटे माइक्रो–फाइनेंस ऋण, जिसमें कुछ सौ रुपये का साप्ताहिक पुनर्भुगतान शामिल है, चुकाया जा रहा है क्योंकि महिला उधारकर्ता रुपये के नोट बटोरने में सक्षम हैं। लेकिन जिन बड़े कर्जदारों को 1000 रुपये से अधिक की किस्त चुकाने की जरूरत है, उनका कहना है कि ऐसा करने के लिए उन्हें करेंसी नोट नहीं मिल रहे हैं।

आरबीआई वित्त कंपनियों के लिए सख्त नियम बनाता है, जिन्हें एक बिंदु से अधिक बकाया ऋणों को संदिग्ध या खराब ऋणों के रूप में वर्गीकृत करना पड़ता है, और अंतर को कवर करने के लिए अलग से धन निर्धारित करना पड़ता है। आरबीआई वित्तीय प्रावधान के लिए अपने नियमों में ढील दे सकता है, और छोटे व्यवसायों और छोटे वित्त को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह और समय बना सकता है। किस तरह की चूक को औपचारिक रूप से विमुद्रीकरण से उत्पन्न असाधारण घटनाओं के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, न कि भुगतान करने में असमर्थता के रूप में?

दीर्घकालिक अर्थ में, काले धन पर युद्ध का भारत की औपचारिक नौकरियों के लिए अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव है क्योंकि पिछले दो दशकों में 100% शुद्ध रोजगार सृजन छोटे, कम उत्पादकता वाले उद्यमों में हुआ है; भारत के 6.3 करोड़ उद्यमों में से 2.4 करोड़ के पास कोई कार्यालय या पता नहीं है, केवल 85 लाख के पास किसी भी प्रकार का कर पंजीकरण है, केवल 15 लाख अनिवार्य भविष्य निधि का भुगतान करते हैं, और केवल 18000 कंपनियों के पास 10 से अधिक की चुकता पूंजी है करोड़ों, केवल 45000 कंपनियों ने देश में किसी भी जॉब पोर्टल पर नौकरी पोस्ट की है। हमारे अधिकांश उद्यम छोटे और अनौपचारिक बने हुए हैं, हमारा 85% विनिर्माण 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों में किया जाता है। यह बड़ी उत्पादकता चुनौतियों का सामना करता है, यदि आप निर्माण कंपनियों को आकार के आधार पर रैंक करते हैं, तो 90 वें प्रतिशतक और 10 वें प्रतिशतक पर फर्मों की उत्पादकता में 22 गुना अंतर होता है; फर्म जो उत्पादक नहीं हैं वे वेतन प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकती हैं। उत्पादकता प्रतिभा और क्रेडिट तक पहुंच से आती है जो औपचारिकता से आती है। अगले दशक में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के उद्यमों की संख्या में 50% से अधिक की गिरावट आएगी, जो स्व–रोजगार को समाप्त कर देगा, जो स्व–शोषण और कम उत्पादकता वाली अनौपचारिक फर्में हैं जो नकदी में काम करती हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था हमारे आकार से 7 गुना अधिक है फिर भी हमारे उद्यमों की संख्या 1/3 है क्योंकि अनौपचारिक उद्यमों को अस्तित्व में रहना और श्रमिकों का शोषण करना बहुत कठिन लगता है।

भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था और सरकार की पहल –

सरकार की पहली पहल नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण थी। विमुद्रीकरण के समय, सकल घरेलू उत्पाद में नकदी का अनुपात 12% था। विमुद्रीकरण के बाद, अनुपात 9% पर आ गया। इस पहल के बाद पेटीएम के 2 मिलियन अतिरिक्त उपयोगकर्ता बढ़े। विमुद्रीकरण के बाद पहले दो दिनों में ट्रैफिक में 700% की वृद्धि और जोड़े गए धन की मात्रा में 1000% की वृद्धि देखी गई। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लेस–कैश सोसाइटी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया है। तीन प्रमुख खिलाड़ी हैं: भुगतान सेवा प्रदाता, अंतर्निहित खाते प्रदान करने वाले बैंक, और एनपीसीआई, जो तत्काल भुगतान सेवाओं के माध्यम से लेनदेन को प्रभावित करने वाले वर्चुअल पेमेंट एड्रेस रिज़ॉल्यूशन को सुनिश्चित करके केंद्रीय स्विच के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खाते से सीधे जुड़े विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ और सब्सिडी को स्थानांतरित करने के लिए एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) शुरू किया। इसने ग्रामीण भारत में डिजिटल बैंकिंग के प्रभाव और पैठ का कारण बना। भारत को कैशलेस बनाने में तेजी लाने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक नीति आयोग समिति की स्थापना की गई है। समिति एक कार्यान्वयन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करती है कि 80% भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चला जाए और सरकार और नागरिकों के बीच सस्ता नकद–आधारित लेनदेन सुनिश्चित करने के उपायों की देखरेख करे। प्रधान मंत्री जन धन योजना भारत

की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है, जिसमें देश के भीतर सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकरण और व्यापक वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है।

विमुद्रीकरण नीति ने अधिकांश भारतीयों के लिए आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर दिया, जो अपने दैनिक जीवन में विशेष रूप से नकदी का उपयोग करते हैं, एक अनुमान के अनुसार 98 प्रतिशत लेनदेन नकद आधारित हैं। हाल के सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि मोटे तौर पर 90 प्रतिशत भारतीय नागरिक अपनी मजदूरी नकद में प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए, जबकि लगभग दो–तिहाई लोग घर पर नकद बचत रखते हैं। इससे पता चलता है कि उनका अधिकांश खर्च नकद में भी किया जाता है, क्योंकि वे वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक–दूसरे को भुगतान करते हैं, या यहां तक कि घर पैसा भेजते हैं (भारत के अधिकांश घरेलू प्रेषण भुगतानों में नकद शामिल है)। संचलन में नकदी की नाटकीय गिरावट ने कुछ भारतीय व्यवसायों को अस्थायी रूप से एक वस्तु विनिमय प्रणाली का सहारा लेने के लिए मजबूर किया है और कुछ मामलों में, हाथ से लिखे IOUs का उपयोग करते हैं ।

निष्कर्ष –

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की राह उतनी आसान भी नहीं है जितनी कि समझी जा रही है। दरअसल केवल युपीआई, पीपीआई और मोबाइल वॉलेट की व्यवस्था से ही अर्थव्यवस्था कैशलेस नहीं हो सकती। इसके लिये हमें जनसंख्या के एक बड़े भाग को बैंकिंग नेट के दायरे में लाना होगा, संगठित क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग काम करें यह सुनिश्चित करना होगा और साथ में कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी जैसी मौलिक आवश्यकताओं का भी ख्याल रखना होगा। कैशलेस अर्थव्यवस्था की डगर मुश्किल तो है लेकिन सरकार भीम एप, लकी ग्राहक योजना, डिजी बैंक योजना, जन–धन योजना आदि जैसे विभिन्न उपाय भी कर रही है। कैशलेस इंडिया एक ऐसा विचार है जिसको व्यावहारिक रूप में अपनाने का उचित समय आ गया है। लेकिन, इसके लिये कारगर उपाय करने होंगे, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी अधिक गतिमान और वृद्धिशाली बनाया जा सके।

संदर्भ –

1. जैन, जे., रमेश, डी., बाबू, सी. और स्टूडेंट (2018)। भारत के संदर्भ में कैशलेस अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का प्रभाव। (ऑनलाइन) 6(1), पीपी. 2320–2882।
2. अस्पताल, जे। (2021)। क्रिप्टो कैशलेस समाज की ओर अगला कदम है। (ऑनलाइन) कॉइनटेग्राफ।
3. भारत में कैशलेस लेनदेनः एक अध्ययन। (रा)। (ऑनलाइन) IJSDR1902011 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च।
4. Proquest-com (2018)। कैशलेस इंडिया की ओर बढ़ते हुए–प्रोक्वेस्ट। (ऑनलाइन)
5. अग्रवाल, कार्तिक; मलिक, सुशांत; मिश्रा, धर्मेश के.; पॉल, दीपेन (2021)। कैश से कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़नाः डिजिटल इंडिया की ओर। द जर्नल ऑफ़ एशियन फ़ाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस, (ऑनलाइन) 8(4), पीपी. 43–54।
6. अखबारः द इकोनॉमिक टाइम्स, दिसंबर 2016 द हिंदू, नवंबर 2016–दिसंबर 2016
7. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/cashless-economy-an-overview.